वर्तमान समय में झारखंड के समक्ष मुख्य चुनौतियाँ व उनके समाधान में पत्रकारिता की भूमिका

[1]पवन कुमार पांडेय

शोध सारांश

झारखंड का अर्थ है - जंगलों का प्रदेश या वो प्रदेश जहाँ जंगल बहुतायत में मिलते हों. इस राज्य का गठन 2000 में किया गया । इससे पहले यह संयुक्त बिहार का हिस्सा था। यहां की अलग जीवनशैली और भौगोलिक स्थिति इसे पूरे देश में विशिष्ट बनाती है। इस राज्य को अलग राज्य बनाने के निर्माण में पत्रकारिता की अहम भूमिका रही है। झारखंड की 26 प्रतिशत आबादी आदिवासी रही है और देश का 40 प्रतिशत खनिज संसाधन भी इस राज्य में मिलते हैं। इसके बावजूद भूखमरी, कुपोषण और ट्रैफिकिंग जैसे राज्य इसके सबसे अहम मुद्दे हैं। आदिवासियों के विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अंग्रेजों ने भी इसे कुछ विशेषाधिकार दिये थे। झारखंड के साथ हमेशा से कुछ मुद्दे जुड़े रहे हैं। नक्सलवाद झारखंड को विरासत में मिली है और आज भी यह समस्या कायम है। छोटे राज्य होने की वजह से स्थापना के शुरूआत के कई वर्षो में यह राजनीतिक रूप से अस्थिर रहा है। इस बीच राज्य बनने के बाद कई अखबारों का प्रकाशन होना शुरू हुआ । धीरे - धीरे झारखंड में राजनीतिक स्थिरता भी बढ़ रही है । वर्ष 2014 में चुनाव के बाद पहली बार झारखंड सरकार पूर्ण कार्यकाल पूरा कर पायी । इससे पूर्व यहा जितनी भी सरकारें आयी कोई कार्यकाल पूरा नहीं कर पायी ।

अलग राज्य आंदोलन के साथ समांतर रूप से यहां की पत्रकारिता ने झारखंड के मुद्दे को राष्ट्रीय फलक में रखा । यहां से निकलने वाले अखबारों ने सत्ता और देश के सीविल सोसाइटी को इसके समाज, संस्कृति और विशिष्ट जरूरतों की ओर ध्यान दिलवाया । प्रस्तुत शोध 20 वर्षो में झारखंड एक राज्य के रूप में कहां तक पहुंचा और यहां की पत्रकारिता के अन्तर्सम्बन्धों का विश्लेषण करता है।

मूल शब्द : झारखण्ड, चुनौतियाँ, पत्रकारिता, संस्कृति ।

Corresponding Author
सहायक प्राध्यापक, जनसंचारविभाग, बीबीएम कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद
email: pandeypawan32@gmail.com

प्रस्तावना

इतिहासकारों का मानना हैं कि इस क्षेत्र को मगध साम्राज्य से पहले भी एक इकाई के रूप में चिन्हित किया जाता था क्योंकि इस क्षेत्र की भू-सरंचना, सांस्कृतिक पहचान अलग ही थी । झारखण्ड राज्य को आदिवासी समुदाय का नैसर्गिक स्थान माना जाता है, जिन्हें भारतीय सविधान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया हैं । जिनमे खड़िया, संताल, मुंडा, हो, उरांव, असुर, बिरजिया, पहाड़िया आदि जातियां प्रमुख हैं। झारखण्ड के जंगलो को साफ कर खेती लायक बनाने तथा मनुष्य के रहने योग्य बनाने का श्रेय इन्ही आदिवासियों को दिया जाता हैं।

महाजनपद काल में झारखण्ड मगध और अंग साम्राज्य का हिस्सा था । मध्य काल में यहाँ पर नागवंशी, खारवेला और चेरो वंश का शासन रहा । वर्ष 1765 में यह इलाका ब्रिटिश सम्राज्य का अधीन हो गया । ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पर अपना शासन जमाया तो उसने जंगल के हिस्से को अपने अधिकार में लेना शुरू किया ताकि यूरोप को कच्चे माल की पूर्ति आसानी से की जा सके । जंगल के संसाधनों पर अपना अधिकार जमा लिया. हजारों वर्षों से उनमें रहते आ रहे आदिवासियों को बेदखल किया जाने लगा ।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इस इलाके में विद्रोह शुरू किया तो कई आदिवासी नेताओं ने बगावत कर दी । यहां के कई आदिवासी समूह को असम के चाय बगानों में मजदूर के रूप में ले जाया गया ।

1771 में तिलका मांझी ने राज महल की पहाड़ियों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोला । फिर 1855 में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ । बिरसा मुंडा ने 1895 -1900 में अंग्रेजों के खिलाफ़ विद्रोह किया । 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस का 53 वां अधिवेशन हुआ । आजादी के बाद जय पाल सिंह मुंडा और राम नारायण सिंह जैसे नेताओं ने एक अलग राज्य की मांग की । पर इस मांग को काफी लम्बे समय तक अस्वीकार किया जाता रहा ।

आजादी के बाद इस आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी रख दिया गया । इस नाम परिवर्तन के पीछे जयपाल सिंह मुंडा का उद्देश्य गैर - आदिवासियों को अपनी पार्टी में जगह देना था । जयपाल सिंह मुंडा की पार्टी झारखंड पार्टी विधानसभा का चुनाव भी लड़ती थी ।

19 72 में बिनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और ए के रॉय ने मिलकर झारखण्ड मुक्ति मोर्चा का गठन किया । निर्मल महतो के द्वारा आजसू का गठन किया गया. इन दोनों पार्टियों ने मिलकर एक अलग राज्य के लिए अभियान चलाया । अगले कुछ दशकों तक यह आन्दोलन चला. इन तमाम वर्षो के बीच आंदोलन चलता रहा । झारखंड राज्य के साथ मुख्य दिक्कत यह थी कि यहां का जो आदिवासी समुदाय है । उसकी जीवनशैली देश के अन्य हिस्सों की जीवनशैली से बिलकुल अलग थी । आदिवासी समुदाय धन संग्रह में विश्वास नहीं करता हैं और मुख्य रूप से गांवों में रहता है । उनके जीविका का आधार वनोत्पाद और खेती है । अगर दूसरे राज्यों में वन रक्षा के लिए कड़ी कानून लगाये जाते हैं लेकिन झारखंड में आदिवासियों का जीविका ही इन वनोत्पाद से चलता है, इसलिए कई ऐसी कानून है जो झारखंड के लिए ठीक नहीं मानी जा सकती है ।

मीडिया और झारखंड की अलग पहचान

संयुक्त बिहार के जमाने से ही झारखंड भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से अलग प्रदेश के रूप में देखा जाता रहा है । यहां रहने वाले लोगों की अपनी समस्याएं रही है । स्वतंत्रता पूर्व आदिवासी समुदाय और अंग्रेज के बीच संघर्ष का इतिहास पाया जाता है ।

इन सब के बीच यहां की पत्रकारिता धीरे - धीरे आकार ले रही थी. अपनी अलग पहचान और अस्मिता की लड़ाई में झारखंड के पत्रकारिता का काफी अहम योगदान रहा है । झारखंड में पत्रकारिता का कोई ज्ञात इतिहास तो नहीं लेकिन रांची एक्सप्रेस यहां की सबसे पुरानी अखबारों में से एक है । रांची एक्सप्रेस के संपादक बलबीर दत्त थे । वहीं धनबाद से 'आवाज'(1947) प्रकाशित होता था । इसके संपादक ब्रम्हदेव शर्मा हुआ करते थे । जमशेदपुर स्टील सिटी से 'चमकता आईना' निकला करता था । इन तीनों अखबारों की काफी प्रतिष्ठा थी और यह कोई कॉरपोरेट घराने की अखबार नहीं थी ।

रांची एक्सप्रेस के संपादक बलबीर दत्त के अनुसार यहां पत्रकारिता करना दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी कठिन था क्योंकि अखबार के हॉकर स्थानीय अखबार को बांटना नहीं चाहते थे । पटना से आया अखबार एक दिन बाद पहुंचता था तो फिर दैनिक अखबार का इस इलाके में कोई मतलब नहीं रह जाता था । दूसकी बात थी कि संयुक्त बिहार की राजधानी पटना से आये अखबार में इस इलाके की खबर न के बराबर थी धीरे - धीरे रांची एक्सप्रेस में यहां की खबरे छपने लगी और अखबार को लोकप्रियता भी हासिल हुई । इन सब के बावजूद ऐसा कोई अखबार नहीं था जो पूरे झारखंड को प्रतिनिधित्व करे. फिर भी इन सब के वजह से एक माहौल बन रहा था और आम लोगों में जागरूकता फैल रही थी ।

इन तीनों अखबारों ने पत्रकारिता की एक पौध तैयार की जो कॉरपोरेट घरानों के अखबार के लिए जमीन का काम करती थी । इसके बाद दैनिक 'आज', 'बिहार ऑब्जर्बर', हिंदुस्तान और प्रभात खबर जैसे अखबार आ गये. हिन्दुस्तान और प्रभात खबर ने पेशेवर रूख अपनाया । कालांतर में दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर ने भी दस्तक दी ।

झारखंड की मूल समस्या की बात करें तो हर क्षेत्र की अलग - अलग समस्या थी. पलामू में सुखाड़ की समस्या थी । संथाल परगना के आदिवासी इलाके में भूखमरी थी. प्रभात खबर ने झारखंड आंदोलन को नयी धार दे दी । यहां के लोगों को स्पेस देना शुरू किया । रामदयाल मुंडा, दयामनी बरला, सूर्य सिंह बेसरा जैसे कई नेता थे, जिन्हें अखबार ने स्पेस देना शुरू किया । यहां के त्यौहार, पर्व और संस्कृति के बारे में विशेष आलेख आने लगे । लिहाजा इसके पाठक तेजी से बढ़ते चले गये । लंबे समय तक प्रभात खबर के प्रधान संपादक रहे हरिवंश जी ने यहां के स्थानीय मुद्दों को तरजीह देना शुरू किया । जिसकी चर्चा देश के अन्य हिस्सों में भी की जाती थी ।

हालांकि जब झारखंड की पत्रकारिता आकार नहीं ली थी । उस वक्त भी देश के कई दिग्गज पत्रकार और साहित्यकार यहां काम करते थे । पलामू के जंगलों में महाश्वेता देवी काम करती थी और उनके कई उपन्यास में केंद्रीय भूमिका में यह इलाका आता है । अकाल की रिपोर्टिंग के लिए लिए अज्ञेय, रघुवीर सहाय, जीतेंद्र सिंह और फणीश्वरनाथ रेणु, पलामू के जंगलों-पहाड़ों में भटके. 'दिनमान', 'धर्मयुग' और 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में इस भूभाग का रिपोर्ट छपा । भूख से मौत की खबरें कई इलाकों से यहां आते रही है ।

कुसुमाटांड गांव मे सूखे की कहानी की सूचना मिलते ही जाने माने अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज (मनरेगा के रणनीतिकार) पहुंचे । वह दिल्ली से रांची आये थे । वहां जाने के बाद उन्होंने वहां की स्थिति देखी की किस तरह से लोग पौधों की जड़े उबाल कर खा रहे हैं और पानी का सैंपल लिया । वहां की सारी बातों को अंग्रेजी के अखबार फ्रंटलाइन में लेख लिखा. इस मार्मिक लेख का काफी असर हुआ । इस तरह से धीरे - धीरे यहां की समस्याओं के बारे में अखबारों ने विस्तार से छापना शुरू किया. झारखंड गठन के बीस साल के बाद भी यहां कुछ समस्याएं जस के तस है।

राज्य के सबसे विकसित जिलों में धनबाद, रामगढ़, रांची, सरायकेला - खरसावां और पूर्वी सिंहभूम शामिल है । वहीं पिछड़े जिलों में पाकुड़, गढ़वा, चतरा, दुमका और गोड्डा शामिल है । अगर झारखंड मौजदा दर से तरक्की करे तो देश की औसत प्रति व्यक्ति आय को हासिल करने में 18 साल लग जायेंगे । प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मणिपुर से अच्छी स्थिति में है । सड़क का औसत घनत्व देश में प्रति हजार किमी पर 182 किलोमीटर है । वहीं झारखंड का 119 है । इस लिहाज से यह सड़क घनत्व में पीछे है । राज्य में 565 किमी रेलवे नेटवर्क पर काम जारी है । राज्य का 91 प्रतिशत आदिवासी समुदाय गांवों में रहती है । वहीं 79.11 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग गांवों में निवास करते है । रोजगार के मामले में झारखंड की बेहतर नहीं कही जा सकती है. झारखंड की बेरोजगारी दर 7.7 वहीं देश का 5.1 है । झारखंड के छह जिलों में ट्रैफिकिंग गंभीर समस्या बनकर उभरी है । इनमें पलामू, दुमका, पाकुड़, रांची, लातेहार, गुमला, सिमडेगा शामिल है ।

वर्तमान समय में झारखंड के समक्ष मुख्य चुनौतियाँ

सामाजिक समस्याएँ

झारखंड गठन के 20 साल के बाद भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो अब भी यहां के समृद्ध जीवन के मार्ग में बाधा है । आज भी यहां भूखमरी और ट्रैफिकिंग सबसे बड़ी समस्याएं हैं । आदिवासी समाज अपने जीवन - यापन के लिए वनोत्पाद पर निर्भर रहता है । इस दिशा में काफी कम काम किये गये हैं । डायन बताकर हत्या करने का मुद्दा झारखंड की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है । देश के 26 प्रतिशत डायन बताकर हत्या का मामला झारखंड से ही आते हैं ।

4 मार्च 2020 को scroll.in में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में अकेले झारखंड राज्य में डायन बता दे बता कर मार देने की घटना 26% अकेले झारखंड में घटी यह रिपोर्ट यह मानती है इसके पीछे का मुख्य कारण यहां की कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था और अशिक्षा है । विच क्राफ्ट प्रीवेंशन एक्ट 2001 के द्वारा इसे रोकने की भरपूर कोशिश की गई है पर यह अभी तक जारी है आपसी दुश्मनी और रंजिश या फिर बदला लेने के लिए भी इस तरह की घटनाओं का सहारा लिया जाता है ।

झारखंड की एक बड़ी समस्या नक्सलवाद रही है । जो करीब - करीब हर जिले में फैल चुकी थी. आज भी यह गंभीर समस्या है । किंतु इसकी धार कम हुई है । चतरा,पलामू, गढ़वा, लातेहार, सिमडेगा जैसे जिले बुरी तरह प्रभावित है । नक्सली संगठनों से हटकर अलग हुए कई टुकड़े संगठनों ने नक्सलवाद के नाम पर सड़क व अन्य ठेकों से रंगदारी मांगने का काम करने लगे हैं ।

ऐसे इलाके जहां पर घने जंगल एवं खनिज पदार्थ की बहुलता है वहां पर नक्सल समस्या अधिक देखने को मिलती है । मल्टीनेशनल कंपनियों ने वहां पर खनिज संसाधनों को निकाल कर उनका दोहन किया अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया पर वहां रहने वाले स्थानीय लोगों का जीवन आज भी गरीबी में ही कट रहा है । इस कारण से एक विचारधारा एक वामपंथी विचारधारा ने वहां पर अपनी जड़े जमाई सन 1967 में नक्सलवाद की शुरुआत हुई जहां पर बंदूक के बल पर अपने अधिकार मांगने की बात कही जाने लगी । नक्सलियों ने डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को मानने से इंकार कर दिया उन्होंने कहा कि यह महज पूंजीपतियों का शासन है । इसमें गरीबों शोषित वंचित हो को न्याय नहीं मिल सकता अगर उन्हें न्याय चाहिए तो उन्हें सत्ता के विरुद्ध बंदूक उठाना होगा । उसके विरुद्ध खूनी संघर्ष करना होगा । नक्सल नक्सलवाद से जुड़े लोगों का यह मानना है की पूंजी पतियों ने आदिवासियों का शोषण किया उनके संसाधन उनसे छीन लिए जिसे दोबारा वह बंदूक के दम पर हासिल करना चाहते हैं ।

झारखंड के कुछ जिलों में पानी में फ्लोराइड की समस्या है । खासकर पलामू और गढ़वा में यहां का पानी पीने हेतु बिल्कुल भी उचित नहीं । पानी में क्लोरीन की मात्रा अधिक होने के कारण पानी में फ्लोराइड अधिक होने के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं । झारखंड के कुछ अन्य जिलों में भी माइंस के कारण कई दुष्प्रभाव देखने को मिले हैं ।

जब से झारखंड एक नए राज्य के रूप में बिहार से अलग हुआ तब यहां पर औद्योगिकरण शहरीकरण माइनिंग अभी के लिए सड़क निर्माण भवन निर्माण के लिए भारी संख्या में पेड़ काटे गए । जंगल की संख्या में बहुत भारी कमी देखी गई है लेट मी ब्रिज की एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के पलामू में टाइगर रिजर्व के नाम पर 3:30 लाख पेड़ों को काटने की योजना सरकार ने 2019 में बनाई झारखंड की सबसे बड़ी पूंजी यहां के जंगल रहे हैं । उस में मिलने वाले संसाधन व खनिज पदार्थ रहे हैं । अगर वही नष्ट हो जाएंगे तो फिर झारखंड में बचेगा क्या इसके नाम का औचित्य है क्या रह जाएगा ? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में साल 2010 से 2019 के बीच में 105 हेक्टेयर जंगल कम हो गए अगर झारखंड में जंगल कम हो जाएंगे तो इससे भूमि कि पानी को स्टोर करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ेगा । जमीन में पानी की भी कमी हो जाएगी, एक तो पहले से ही यहां पर गहरी नदिया नहीं है । आज ही रांची बोकारो धनबाद जैसे कई इलाकों में पानी का विचित्र संकट देखने को मिल रहा है ।

मीडिया की संभावित भूमिका

झारखंड में मीडिया की भूमिका काफी सकरात्मक रही है । राज्य गठन के पूर्व भी यहां की जीवनशैली, संस्कृति दिल्ली में सत्ता में बैठे लोगों के बीच अबूझ पहेली जैसी थी । मीडिया ने उन्हें इसकी विशिष्टता का अहसास दिलाया । यहां के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आंदोलनकारियों को जगह देना शुरू किया और एक प्रबुद्ध नागरिक का वर्ग तैयार किया जो अपने हक के लिए आवाज उठा सके ।

राज्य गठन के बाद झारखंड को एक सीविल सोसाइटी की जरूरत थी । क्योंकि सीविल सोसाइटी 'बफर जोन' तैयार करती है । यह एक किस्म से नागरिक और सरकार के बीच सेतु की तरह है । आज भी समाज का निचला तबका अपने लिए आवाज नहीं उठा पाता है । ऐसे में सिविल सोसाइटी उनके विकास के लिए कदम उठा सकती है । सरकार को हमेशा यह सोचना चाहिए की उद्योग जरूरी है लेकिन झारखंड जैसे राज्य में एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था चाहिए जो यहां के जरूरतों के हिसाब से तैयार हो । पर्यटन, खेती, खेल, वनोत्पाद और कला को बढ़ावा देकर ही यहां के राज्य के लोगों का जीवन समृद्ध किया जा सकता है । मीडिया को हमेशा ग्रामीण और दूरदराज

के इलाकों की रिपोर्टिंग करनी चाहिए । अभी भी ज्यादा कवरेज शहरों को दिया जाता है । जबकि मूलरूप से झारखंड एक ग्रामीण राज्य है और दूसरे राज्यों की तुलना में यहां शहरीकरण कम है ।

मीडिया की एक बड़ी जिम्मेवारी पॉलिसी निर्माण में सरकार को सुझाव देने की होती है क्योंकि जमीनी सच्चाई मीडिया के द्वारा ही पता चला सकता है । झारखंड की पहचान सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य के रूप में होती है । जनजाति समुदाय में निरक्षरता और गरीबी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है । इसमें सुधार की गुंजाइश है ।

डिजिटलाइजेशन के इस दौर में सोशल मीडिया बहुत ही प्रभावी और उपयोगी संसाधनों में से एक है रीयल टाइम समाचार एवं महत्वपूर्ण संदेशों का आदान.प्रदान सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है । जिससे तेजी से जागरुकता फैली है । कोरोना महामारी के वक्त सोशल मीडिया के प्लेटफार्म का सरकार ने जमकर उपयोग किया । सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए और छोटे - छोटे जगहों से ऐसी परिस्थिति में खबरें लायी जा सकती है। कई जगहों पर मजदूर फंसे थे । इस दिशा में हेमंत सोरेन सरकार ने अच्छा प्रयास किया है और अच्छे गवर्नेंस के लिए ट्वीटर का जमकर प्रयोग किया है ।

झारखण्ड आदिम संस्कृति की भूमि रही है । छोटानागपुर का पठार दुनिया के सबसे प्राचीन भूभागों में से एक है.सौ साल पहले तक यह बंगाल प्रान्त का हिस्सा था । बाद में बिहार का अंग रहा. और साल 2000 में अलग राज्य बना । आजादी के बाद से ही स्वतंत्र राज्य के लिए आन्दोलन चला । जयपाल सिंह मुंडा ने लोक सभा में इस प्रश्न को उठाया ।

Building Solidarities: A Case of Community Radio in Jharkhand

hala Ho Gaon Mein' is indeed a unique experiment in using media technologies, especially radio, for development and empowerment of marginalised, rural communities. Designed a community-driven project, it takes on a special significance in an economically deprived area, marked by illiteracy and relatively indifferent attitude of the state as well as the mainstream media towards the problems of the region. Within a short time, the programme has generated a great

deal of enthusiasm among the people. Listeners not only feel that the programme is geo- graphically and culturally more intimate to their lives, but gradually, a sense of attachment to the programme is beginning to build up. Suppressed local artistic talents have come to fore, women caught up within feudal social structures are ginning, albeit very slowly, to find a voice of their own, there is a sense of optimism that the radio programme would help solve many of the intractable problems of

तो प्रश्न अब यह उठता है कि झारखंड की समस्याओं को सुलझाने में मीडिया की संभावित भूमिका क्या हो सकती है हमने अभी तक झारखंड की कई समस्याओं पर नजर डाला है लेकिन इसमें मीडिया इन्हें समझाने में क्या मदद कर सकता है । यह अब देखेंगे case of कम्युनिटी रेडियो इन झारखंड नाम के एक पेपर में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी मीडिया के प्रोफेसर डॉ विनोद पवराला ने झारखंड के पलामू जिले में किए शोध में पाया कि वहां की समस्याओं से निबटने में कम्युनिटी रेडियो यानी सामुदायिक रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है ।

निष्कर्ष

झारखंड एक नवगठित राज्य है । किसी भी राज्य को ठीक ढंग से संचालित करने के लिए कुछ सजग नागरिकों की आवश्यकता होती है । ऐसे सजग नागरिकों के समूह के निर्माण करने में मीडिया की भूमिका अहम रहती है । । चूंकि यहां पहले से शासन का अनुभव नहीं है, इसलिए कई तरह की आरंभिक परेशानी आयी । वक्त के साथ उन दिक्कतों को प्रकाश में लाने का काम मीडिया ही करता है । भविष्य में मीडिया जितनी मजबूत और सशक्त होगी । झारखंड एक राज्य के रूप में उतना सशक्त होगा और उसकी जड़े गहराई तक पहुंचेगी । अभी जो झारखंड में मीडिया की स्थिति है । वह सिर्फ सूचना देने तक सीमित है । सालों पहले झारखंड की स्थिति का चित्रण करते हुए महाश्वेता देवी ने एक उपन्यास लिखा था - जंगल के दावेदार । जो उस समय की मौजूदा स्थिति को दिखाती थी । इस मार्मिक उपन्यास के जरिये आदिवासियों के जीवन का चित्रण किया गया था ।

एक दूसरा पहलू झारखंड की संस्कृति, जीवनशैली और भौगोलिकता का भी है । यह देश के दूसरे हिस्सों की तरह नहीं है । झारखंड और छतीसगढ़ में काफी समनाताएं है. सरकार अगर आदिवासी समुदाय तक नहीं पहुंचेगी । उसके साथ अगर संवाद कायम नहीं कर पायेगी तो फिर इसका लाभ अलगाववादी संगठन उठा सकते हैं । उनसे संवाद करने का तरीका भी काफी अलग होना चाहिए । मुख्यधारा की मीडिया उनकी भाषा में बात नहीं कर सकती । इसलिए लोक माध्यम की जरिये उनसे आसानी से जोड़ा जा सकता है । भारत में जितनी विविधता है । उतनी विविधता झारखंड में भी है । आदिवासी, गैर - आदिवासी, बाहर से आये प्रवासियों की बड़ी संख्या यहां निवास करती है । वह भी वर्षो से यहां रहते आये हैं । ऐसे में उनके हित की बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए । एक ऐसा राज्य जो बहुसांस्कृतिक हो वहां के सभी समुदायों के प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है । झारखंड मुख्यत: आदिवासी राज्य है लेकिन इसकी सच्चाई यह भी है कि गैरआदिवासियों की संख्या है । वहीं बाहर से आये प्रवासियों की भी भारी संख्या में मौजूदगी है । ऐसी स्थिति में सभी समुदाय का प्रतिनिधत्व हो, वह सुनिश्चित करना आवश्यक है । अभी तक झारखंड के पूरे समाज में एकरसता नहीं है और हमेशा मूलवासी और बाहर से प्रवासियों का मुद्दा उठता रहता है । इस स्थिति का कोई हल निकाला जाना चाहिए ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

पावरला ,भी . (2003)बिल्डिंग सोलिडरीटीएस : ऐ केस ऑफ़ कम्युनिटी रेडियो इन झारखण्ड इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली , मई 31 - Jun. 6, 2003, Vol. 38, No. 22 pp. 2188-2197.

कुमार,एस,(2018)आदिवासिस एंड दी पॉलिटिक्स इन झारखण्ड https://doi.org/10.1177/2321023018762821

https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IND/15/ accessed **18th November 2022.**

https://www.sundayguardianlive.com/news/jharkhands-maoist-affected-districts-gradually-returning-mainstream accessed **20th September 2022.**

https://scroll.in/article/955045/whats-to-blame-for-jharkhands-witch-hunting-problem-poor-healthcare-and-illiteracy accessed **18th November 2022.**

https://www.firstpost.com/india/the-witches-of-jharkhand-from-ignorance-to-land-grabs-what-fuels-witchcraft-in-the-mineral-rich-state-7033771.html accessed **20th September 2022.**

https://www.hindustantimes.com/ranchi/contaminated-water-the-silent-killer-in-this-jharkhand-village/story-mBlXle9vCFGkgR2sVYqTTJ.html accessed **15th August 2022.**

https://www.prabhatkhabar.com/state/jharkhand/522188 accessed **10th September 2022.**